भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2934
जिसका उत्तर मंगलवार, 29 मार्च, 2022
8 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है।

बीपीसीएल के निजीकरण का प्रभाव

2934 श्रीमती फूलो देवी नेतमः
श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ लागू करने की मंशा है कि ऊर्जा क्षेत्र की किसी भी प्रमुख घरेलू कंपनी में विदेशी कंपनियों बहुमत में हिस्सेदारी न प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बीपीसीएल की बिक्री के बाद डीज़ल और पेट्रोल के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाएगा;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की यह किस प्रकार सुनिश्चित करने की योजना है कि राज्य के स्वामित्व वाले शोधनकर्ताओं पर बाज़ार की ताकतों का नकारात्मक प्रभाव न पड़े; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा बीपीसीएल की बिक्री सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को प्रभावित करेगी, यदि हाँ, तो इसे किस प्रकार संभाला जाएगा?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क) से (ड.): पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाज़ार द्वारा निर्धारित की गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में संबंधित उत्पादों की क़ीमतों से जुड़ी हुई हैं। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी पेट्रोल और डीज़ल की कीमत निर्धारण पर समुचित निर्णय लेते हैं। सरकार ने एफडीआई पर नीतिगत ढांचा प्रस्तुत किया है जो कि पारदर्शी, पूर्वानुमेय, आसानी से बोधगम्य है। सरकार बीपीसीएल के विनिवेश के बाद भी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं देखती है।

*****